

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ,  
अपर आमवाला, देहरादून।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 02 अक्टूबर, 2017

**विषय:-**वित्तीय वर्ष 2017-18 में नई मांग के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(I)/2017 दिनांक 30.06.2017 एवं आपके पत्र संख्या-1922/आई.आर.डी.टी./नई मांग/2017-18 दिनांक 09.10.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में नई मांग के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 4990 हजार (उन्नचास लाख नब्बे हजार मात्र) को निम्न लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि में से मानक मद-16 को अग्रिम के रूप में आहरित किया जायेगा तथा शेष धनराशि को नियमानुसार व्यय हेतु कोषागार से आहरित किया जायेगा।
3. उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-11 के प्राविधानानुसार आवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के 'अनुदान संख्या-11' के लेखाशीर्षक संख्या-"2203-तकनीकी शिक्षा-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-00-04- संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ " के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।



3- यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति / बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक-1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*(हस्ताक्षर)*

(जी.एस. बिष्ट)

उप सचिव।